नईदुनिया

ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो तख्तापलट साजिश मामले में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए

रियो डी जनेरियो

ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो मंगलवार को देश की सर्वोच्च अदालत के समक्ष एक कथित तख्तापलट योजना में पहली बार गवाही देने के लिए पेश हुए। यह मामला वर्ष 2022 के राष्ट्रपति चुनाव परिणाम को पलटने और सत्ता में बने रहने की कथित साजिश से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट की एक विशेष पीठ इस बहुचर्चित मामले की सुनवाई कर रही है, जिसमें बोल्सोनारो सहित उनके सात प्रमुख सहयोगियों पर पांच गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोपों में तख्तापलट की कोशिश, सशस्त्र आपराधिक संगठन में संलिप्तता, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को बलपूर्वक समाप्त करने का प्रयास, राष्ट्रीय धरोहर को नुकसान पहुंचाना और उसकी क्षति करना शामिल है। अगर बोलसोनारो पर तख्तापलट का आरोप सिद्ध होता है, तो उन्हें 12 साल तक की जेल की सजा हो सकती है, और अन्य आरोपों के साथ कुल सजा कई दशकों तक बढ़ सकती है। पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। उनके साथ पूर्व रक्षा मंत्री और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार वॉल्टर ब्रागा नेटो, पूर्व मंत्री एंडरसन टोरेस, ऑगस्टो हेलेनो और पूर्व सहयोगी मौरो सिड जैसे प्रमुख नाम भी इस मामले में आरोपित हैं। हालांकि बोल्सोनारो के पूर्व सहयोगी मौरो सिड ने पुलिस से गोपनीय समझौता (प्ली बार्गेन) किया है और अदालत में गवाही देते हुए बताया कि बोल्सोनारो ने उस दस्तावेज को पढ़ा और संपादित किया था, जिसमें चुनाव परिणाम को अमान्य करने की योजना थी। सिड ने यह भी दावा किया कि बोल्सोनारो ने अपने समर्थकों द्वारा सेना मुख्यालयों के बाहर लगाए गए शिविरों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। यही समर्थक बाद में 08 जनवरी 2023 को ब्रासीलिया में हुई हिंसा में शामिल पाए गए, जब सुप्रीम कोर्ट, संसद और राष्ट्रपति भवन पर हमला किया गया। ब्राजील के अटॉर्नी जनरल पाउलो गोनेट ने अदालत में दावा किया कि यह दंगा उस बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य चुनाव परिणाम को पलटना था। उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एलेक्जेंडर डी मोराइस की हत्या की भी योजना थी, जो अंतिम क्षणों में इसलिए टल गई क्योंकि सेना प्रमुख ने इसमें सहयोग नहीं किया।

न्यूज ब्रीफ

हमास को फंडिंग के आरोप में अमेरिका ने कथित 'फर्जी' फिलीस्तीनी चैरिटियों पर लगाया प्रतिबंध

वॉशिंगटन। अमेरिका ने मंगलवार को एक बड़ा कदम उठाते हुए मध्य पूर्व, अफ्रीका और यूरोप में फैले पांच लोगों और पांच संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने इन पर हमास के सैन्य विंग को आर्थिक मदद पहुंचाने का आरोप लगाया है। इन संस्थाओं पर यह भी आरोप है कि वे गाजा पट्टी और अन्य क्षेत्रों में मानवीय कार्यों की आड़ में आतंकी फंडिंग कर रह थे। प्रतिबंधित संस्थाओं में प्रमुख नाम: अल-विआम चैरिटेबल सोसाइटी (गाजा स्थित): इस पर आरोप है कि यह हमास के नियंत्रण में है। इसके कार्यकारी निदेशक मोहम्मद सामी मोहम्मद अबू मरेई को भी प्रतिबंधित सूची में शामिल किया गया है। फिलिस्तीन वक्फी (तुर्की आधारित): इस चैरिटी और इसके अध्यक्ष जेकी अब्दुल्ला इब्राहीम अररावी पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। अन्य देश: अल्जीरिया, नीदरलैंड और इटली में स्थित कुछ अन्य चैरिटियों को भी प्रतिबंधित किया गया है, जिनके हमास या फिलिस्तीनी कट्टरपंथी समूहों से कथित संबंध हैं। इसके अलावा अमेरिका ने एक और संस्था पर भी कार्रवाई की है, जो फिलिस्तीनी संगठन 'पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन' (पीएफएलपी) से जुड़ी बताई जा रही है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग की 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आतंकी वित्तपोषण के लिए अब ऑनलाइन क्राउड फंडिंग का सहारा लिया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चूंकि अधिकांश ऑनलाइन फंडिंग वैध सामाजिक कार्यों के लिए होती है, इसलिए आतंकी फंडिंग की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि सुरक्षा एजेंसियों को जांच में अधिक जटिलता का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ये प्रतिबंध इस बात का स्पष्ट संदेश है कि अमेरिका आतंकवाद के लिए आर्थिक सहायता के किसी भी रास्ते को बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वह मानवीय सेवा की आड़ में ही क्यों न हो।

हिरासत में लिए गए दुनिया के सबसे बड़े टिकटॉक स्टार खाबी लेम, छोड़ना पड़ा अमेरिका

लास वेगास। वीसा संबंधी शर्तों के उल्लंघन के आरोप से घिरे विश्व में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले टिकटॉक स्टार खाबी लेम ने अमेरिका छोड़ दिया है। उनको अमेरिका में इमिग्रेशन और कस्टम्स एनफोर्समेंट (आईसीई) ने हिरासत में लिया था, जिसके बाद उन्होंने स्वेच्छा से देश छोड़ दिया। सेनेगल में जन्मे और इटली के नागरिक खाबी लेम का असली नाम सेरिंगे खाबाने लामे है। उनको 6 जून को लास वेगास के हैरी रीड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया था। आईसीई के प्रवक्ता के अनुसार, लामे ने अपने वीजा की शर्तों का उल्लंघन किया था, क्योंकि वे 30 अप्रैल को अमेरिका आए थे और निर्धारित समय से अधिक रुके थे। लेम की हिरासत उस समय हुई, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई सरकार ने आप्रवासन पर सख्ती बढ़ा दी है। ट्रंप ने अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए बड़े पैमाने पर निर्वासन अभियान शुरू किया है, जिसके तहत आईसीई ने पूरे अमेरिका में छापेमारी की है। लॉस एंजिल्स में हाल ही में हुई आईसीई की छापेमारी ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया, जहां प्रदर्शनकारियों ने हम नहीं जाएंगे और हम यहां विरोध करने आए हैं जैसे नारे लगाए। ट्रंप ने इन प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिए नेशनल गार्ड को तैनात किया, जिसका कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूजम और लॉस एंजिल्स की मेयर करेन बास ने विरोध किया।

अल कायदा ने ट्रंप, मस्क को दी जान से मारने की धमकी, हिट लिस्ट में कई नाम

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की धमकी दी गई है। खबर है कि एक्यूएपी यानी अल कायदा इन अरबियन पेनिन्सुला ने ट्रंप को मारने का संदेश जारी किया है। हालांकि, इसे लेकर अमेरिका की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। लिस्ट में ट्रंप के अलावा उनकी सरकार के और लोगों के भी नाम हैं। सामने आए वीडियो में इस धमकी की वजह गाजा में हो रही हिंसा को बताया जा रहा है। बता दें कि एक्यूएपी को अल कायदा की सबसे खतरनाक शाखा माना जाता है। अल अव्लाकी पर अमेरिका ने 60 लाख डॉलर के इनाम का ऐलान किया है। करीब आधे घंटे के इस वीडियो में ट्रंप और मस्क के अलावा उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के चेहरे नजर आ रहे हैं। इनके अलावा मिस्र, जॉर्डन और खाड़ी के अरब देशों में नेताओं को मारने की अपील की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, एक्यूएपी चीफ ने अमेरिका में रहने वाले लोगों से गाजा में हो रहे युद्ध का बदला लेने की अपील की है।

पाकिस्तान : अहमदिया समाज को बकरीद के दिन नमाज नहीं पढ़ने दी और कुर्बानी से भी रोक दिया

इस्लामाबाद

पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय को ईद-उल-अजहा के मौके पर कम से कम सात शहरों में नमाज अदा करने और कुर्बानी देने से रोक दिया गया। जमात-ए-अहमदिया पाकिस्तान (जेएपी) ने आरोप लगाया कि स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से यह उत्पीड़न किया गया। जेएपी के अनुसार, पंजाब पुलिस ने दो अहमदियों को गिरफ्तार किया और तीन के खिलाफ केस दर्ज किया गया। आरोप है कि वे परंपरागत कुर्बानी देने की कोशिश कर रहे थे, जिसे पाकिस्तान में अहमदियों के लिए प्रतिबंधित किया गया है।

अहमदियों को जिन शहरों में ईद की नमाज पढ़ने से रोका गया, उनमें खुशाब, मीरपुर खास, लोधरां, भक्कर, राजनपुर, उमरकोट, लरकाना और कराची शामिल हैं।पंजाब पुलिस ने पुष्टि की कि उन्होंने दो अहमदियों को गिरफ्तार किया और तीन के खिलाफ कार्रवाई की। वहीं, जमात-ए-अहमदिया ने इस कदम को न सिर्फ भेदभावपूर्ण बल्कि संविधान के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के संविधान का अनुच्छेद 20 हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन अहमदियों को यह अधिकार नहीं दिया जा रहा। यह घटना ऐसे समय पर हुई है जब अहमदिया समुदाय पर हमलों की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। मई में एक वरिष्ठ अहमदिया डॉक्टर की हत्या की गई थी और पंजाब में 100 से अधिक अहमदिया कब्रों को अपवित्र किया गया था। 1974 में पाकिस्तान की संसद ने अहमदियों को गैर-मुस्लिम घोषित किया था और 1984 में उनके लिए इस्लामिक प्रतीकों और रिवाजों का पालन करना भी गैरकानूनी बना दिया गया।जेएपी ने कहा, संगठनों का बढ़ता दुस्साहस हमारे समुदाय की सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है। जबरन धर्मांतरण और धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन हैं।

अमेजन जंगलों की खास चाय विदेशी पर्यटकों में मशहूर, यह एक तरह का नशा

लीमा। पेरू के घने अमेजन जंगलों में 41 साल के अमेरिकी पर्यटक की एक धार्मिक अनुष्ठान के दौरान मौत हो गई। वजह थी एक खास तरह की चाय, जिसे 'आयाहुआस्का' कहते हैं. यह कोई आम चाय नहीं, बल्कि एक ऐसा नशा है, जो दिमाग को झकझोर देता है और अमेरिका जैसे कई देशों में पूरी तरह प्रतिबंधित है, लेकिन फिर भी, यह चाय विदेशी पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है। आयाहुआस्का एक खास तरह का पेय है, जो अमेजन के जंगलों में पाए जाने वाले पौधों से तैयार किया जाता है। इसमें डीएमटी नाम का एक ताकतवर रसायन होता है, जो दिमाग को गहरे मतिभ्रम में ले जाता है। अमेजन के आदिवासी इसे सैकड़ों सालों से धार्मिक और मेडिकल के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उनके लिए यह चाय आत्मा को शुद्ध करने और आध्यात्मिक ज्ञान पाने का जरिया है, लेकिन पिछले कुछ सालों में, यह विदेशी पर्यटकों के लिए एक नया 'एडवेंचर' बन गया है। लोग मानसिक शांति, डिप्रेशन से छुटकारा, या फिर एक अनोखे अनुभव के लिए इसे आजमाने पेरू, बोलीविया जैसे देशों में पहुंच रहे हैं। 41 साल के अमेरिकी पर्यटक की इसे पीने से हुई मौत आरोन जो अमेरिका के अलबामा से थे, पेरू के लोरेटो इलाके में एक होस्टल, 'ला कासा दे गुइलेर्मो आइकोना' में रुके थे। यह होस्टल 'आध्यात्मिक पर्यटन' के लिए मशहूर है। यहां लोग आयाहुआस्का अनुष्ठानों में हिस्सा लेने आते हैं, जिन्हें स्थानीय शमैन आयोजित करते हैं। विगत सोमवार को हुए एक ऐसे ही अनुष्ठान में आरोन ने आयाहुआस्का चाय पी थी, लेकिन इसके बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी। स्थानीय फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट के मुताबिक इस चाय ने उनके शरीर के कई अंगों को पूरी तरह से बेकार कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। होस्टल के मैनेजरों का कहना है कि आरोन ने आयोजकों को यह नहीं बताया कि वे पहले से एंटीबायोटिक दवाइयाँ ले रहे थे। ऐसा माना जा रहा है कि इन दवाइयों और आयाहुआस्का के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया ने उनकी हालत को बिगाड़ दिया। आयाहुआस्का कोई साधारण पेय नहीं है। यह चाय पीने के बाद लोग घंटों तक मतिभ्रम की दुनिया में चले जाते हैं।

लॉस एंजिल्स में प्रवासी विरोध प्रदर्शन के बीच ट्रंप ने की मरीन तैनाती, उठे सवाल

वाशिंगटन

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रवासियों के खिलाफ जारी प्रदर्शनों को रोकने के लिए लॉस एंजिल्स में सैकड़ों मरीन तैनात करने के आदेश दिए हैं। मंगलवार को लगभग 700 अमेरिकी मरीन सैन्य वाहनों के साथ शहर के बाहर एक अस्थायी स्थल पर पहुंचे। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने 4,000 नेशनल गार्ड जवानों को भी सक्रिय कर दिया है।

व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर सैन्य बलों की तैनाती नहीं होती, तो लॉस एंजेलेस अभी तक जल चुका होता। उन्होंने संकेत दिया कि यदि स्थिति और बिगड़ती है, तो वे इन्सरेक्शन एक्ट लागू कर सकते हैं, जो सेना को नागरिक कानून व्यवस्था संभालने की अनुमति देता है। ट्रंप ने कहा कि हम कोई खतरा नहीं उठा सकते। लॉस एंजिल्स के कुछ हिस्सों में पहले से ही बगावत जैसे हालात हैं।

अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि तैनात मरीन केवल संघीय संपत्तियों और अधिकारियों की सुरक्षा करेंगे। उन्हें आम नागरिकों की गिरफ्तारी का अधिकार नहीं होगा। सैन्य बलों की तैनाती की कुल लागत करीब 134 मिलियन डॉलर बताई जा रही है, जिसमें आवास, भोजन और यात्रा शामिल हैं।

वहीं, कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम और लॉस एंजिल्स की मेयर करेन बैस ने ट्रंप के जवानों की तैनाती के कदम को अत्यधिक और अनावश्यक बताया है। राज्य के अधिकारियों के अनुसार, प्रदर्शन ज्यादातर शांतिपूर्ण रहे हैं और ट्रंप प्रशासन की कार्रवाई जरूरत से ज्यादा आक्रामक है।

गवर्नर न्यूसम ने सोशल मीडिया पर इस फैसले की आलोचना करते हुए लिखा, सोचिए, अगर यही राशि पूर्व सैनिकों के पोषण और आवास पर खर्च होती तो कितना अच्छा होता, बजाय इसके कि सैनिकों को राजनीतिक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है।

बांग्लादेश के 369 जायरीन पहली वापसी हज उड़ान से स्वदेश लौटे

सऊदी अरब से हज वापसी उड़ानों का आगमन शुरू हो गया। 369 बांग्लादेश के यात्रियों को लेकर पहली वापसी हज उड़ान कल सुबह 10:54 बजे राजधानी ढाका के हजरत शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। हवाई अड्डा प्राधिकारियों ने बयान जारी कर यह जानकारी दी। खबर के अनुसार, हवाई अड्डा प्राधिकारियों ने कहा कि सऊदी अरब का विमान एसवी-3803 इन्हें लेकर पहुंचा। स्वदेश लौटे जायरीनों का बोर्डिंग गेट पर फूलों से स्वागत किया गया। बिमान बांग्लादेश एयरलाइंस के बूथ पर उन्हें जमजम पानी की बोतलें दी गईं। बांग्लादेश के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के अध्यक्ष एयर वाइस मार्शल मोहम्मद मोनजुर कबीर भुइयां व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहे। बांग्लादेश धार्मिक मामलों के मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार, कल 12 उड़ानों से 4,904 तीर्थयात्री वापस लौटने वाले थे। मगर कल एक ही विमान आ सका। हज उड़ानों का वापसी चरण 10 जुलाई तक जारी रहेगा। इस साल बांग्लादेश के कुल 86,958 जायरीनों ने हज किया। कुल 222 उड़ानें सऊदी अरब से तीर्थयात्रियों को बांग्लादेश वापस लाएंगी।

पाकिस्तान रेल सेवाओं का रूस तक विस्तार करेगा, 22 जून से शुरू होगा काम

इस्लामाबाद

पाकिस्तान के रेलमंत्री हनीफ अब्बासी ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी रेल सेवाओं का रूस तक विस्तार करने जा रहा है। इस पर 22 जून से काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने पत्रकारों को यह जानकारी मंगलवार को पंजाब प्रांत के मुल्तान रेलवे के डिवीजनल सुपरिंटेंडेंट के कार्यालय में आहूत प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी।

खबर के अनुसार, अब्बासी ने कहा कि यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 2027 तक रेलवे के बेड़े में करीब 200 गाड़ियां शामिल की जाएंगी। रेलवे का तेजी से डिजिटलीकरण किया जा रहा है। इस संबंध में पंजाब सूचना प्रौद्योगिकी बोर्ड के साथ करार हो चुका है।

उन्होंने कहा कि जल्द ही देश की सभी ट्रेनों में मुफ्त वाईफाई सेवा प्रदान की जाएगी।

उन्होंने कहा कि ट्रेनों को समय पर चलाने के लिए यथासंभव प्रयास किए जा रहे हैं। रेलमंत्री ने साफ किया कि रेलवे रणनीतिक संपत्ति है। इसलिए उसे पूरी तरह आउटसोर्स नहीं किया जा सकता। रेलवे ने 31 मई तक अपने इतिहास में सबसे अधिक राजस्व अर्जित किया है। उम्मीद है कि यह 30 जून तक नई ऊंचाइयों को छू लेगा।

रेलमंत्री ने कहा कि वर्तमान में 11 ट्रेनों को आउटसोर्स किया जा रहा है। 155 रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड किया गया है। रेलवे के आठ अस्पतालों और 14 स्कूलों को भी आउटसोर्स किया जा रहा है। स्टेशनों और ट्रेनों के अंदर खाद्य पदार्थों के गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित किया गया है। रेल पटरियों के किनारे फलदार पेड़ लगाने के लिए वन विभाग के साथ करार किया गया है।

अमेरिका में प्रोटेस्टेंटवादियों का एसबीसी में समलैंगिक विवाह के खिलाफ मतदान

डलास (टेक्सास)

दक्षिणी बैपटिस्ट कन्वेंशन (एसबीसी) ने मंगलवार को यहां अपनी सालाना बैठक में सुप्रीम कोर्ट के 10 वर्ष पुराने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाले ऐतिहासिक फैसले के विरोध में पारित प्रस्ताव के समर्थन में भारी मतदान किया। प्रस्ताव में मांग की गई है कि ओबर्गेफेल बनाम होजेस मामले को पलटने का समय आ गया है। दक्षिणी बैपटिस्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा प्रोटेस्टेंट संप्रदाय है।

खबर के अनुसार, डलास में 10 जून को दक्षिणी बैपटिस्ट कन्वेंशन की बैठक में किया गया मतदान ओबर्गेफेल बनाम होजेस मामले को पलटने की दिशा में किए जा रहे अब तक के प्रयासों का बड़ा अभियान है। इससे समलैंगिक विवाह के खिलाफ मजबूत समर्थन जुटाया जा सकता है। पिछले साल भी वार्षिक बैठक में प्रस्ताव पारित कर इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) के उपयोग की निंदा की गई थी।

इस साल के प्रस्ताव में जिक्र किया गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरा कार्यकाल शुरू करते ही एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। यह आईवीएफ के बढ़ते प्रचलन को हतोत्साहित करता है। प्रस्ताव में जोर देकर विवाह को सिर्फ एक पुरुष और एक महिला के बीच परिभाषित किया गया है। इसकी व्याख्या में कहा गया है कि परिवार प्रजनन के लिए बनाए गए हैं और मानव जीवन गर्भाधान से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक पवित्र है। यह वैवाहिक बंधन ईसाई मान्यताओं के अनुरूप है। यह सार्वभौमिक सत्य है। साथ ही स्वस्थ, न्यायपूर्ण और स्वतंत्र समाज के लिए आवश्यक है। प्रस्ताव में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वेच्छा से संतानहीनता को मान्यता प्रदान करता है। यह प्रजनन दर की गिरावट में योगदान देता है। पुरुष और महिला के बीच जैविक अंतर को अनदेखा करता है। माता-पिता के अधिकारों को सीमित करने वाला है। इससे बच्चों के मूल्यों और गरिमा को भी आघात पहुंचता है। यह फैसला समाज को विकृत भी कर रहा है। प्रस्ताव में वाणिज्यिक सरोगेसी और ट्रांसजेंडर विचारधारा के सामान्यीकरण का भी विरोध किया गया है। इसमें कहा गया है कि पुरुष और महिला की जैविक वास्तविकता को नकारने वाली नीतियां कानूनी कल्पनाएं हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि पिछले साल सालाना दक्षिणी बैपटिस्ट कन्वेंशन ने महिला पादरियों पर संवैधानिक प्रतिबंध को संकीर्ण बताते हुए खारिज कर दिया था। साथ ही एसबीसी ने सात चर्चों को को बहिष्कृत करने की घोषणा की थी।इसमें दक्षिणी कैलिफोर्निया का मेगाचर्च सैडलबैक भी शामिल था। सुप्रीम कोर्ट के दक्षिणपंथी झुकाव और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जीत से खुश एसबीसी के अधिक रूढ़िवादी गुट और ईसाई राजनीतिक कार्यकर्ता इस परिदृश्य को अमेरिकी न्यायशास्त्र में बदलाव के लिए उपयुक्त मानते हैं। कन्वेंशन में केंद्रित संगठन फेथ विन्स के चैड कोनेली ने कहा कि अब बदलाव का सही समय है। इस वर्ष का संकल्प समलैंगिक विवाह की रक्षा करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पुरजोर विरोध करना है। यह प्रस्ताव एसबीसी में डेनी बर्क ने प्रस्तुत किया। बर्क इस समय लुइसविले स्थित काउंसिल फॉर बाइबिलिकल मैनहुड एंड वूमनहुड के अध्यक्ष हैं। इसमें शामिल वकील एलजीबीटीक्यू को प्रदत्त किए गए अधिकारों का विरोध करते हैं। वकीलों के इस समूह के दो स्टेटमेंट चर्चा में रहे हैं। पहला स्टेटमेंट 1987 में डेनवर स्टेटमेंट था और दूसरा 2017 में नैशविले स्टेटमेंट था। नैशविले स्टेटमेंट में कहा गया है कि समलैंगिक अनैतिकता या ट्रांसजेंडरवाद को मंजूरी देना पाप है। इस तरह स्वीकृति ईसाई विश्वास पर चोट करती है।